

पेंशनर्ज को कर्मचारियों के वेतन से पहले मिलेगी पेंशन : डॉ. राजेश

■ एच.पी. शिक्षा बोर्ड में 'सच्चीचौपाल', पेंशनरों को मिला सम्मान और बकाया राशि का आश्वासन

धर्मशाला, 18 फरवरी (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में आयोजित 'पेंशनर महामंथन सम्मेलन' में पूर्व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और बोर्ड के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कार्यक्रम को 'सच्ची चौपाल' का नाम दिया गया, जहां पेंशनरों को सम्मानित करने के साथ-साथ उनके लंबित वित्तीय मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए गए। इसके साथ ही पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया, जिसे सच्ची चौपाल भी दिया गया।

उन्होंने कहा कि 85 करोड़ सरकार व शिक्षा विभाग से लेने को हैं, जोकि जल्द मिल जाने पर वित्तीय संकट से उभर सकेंगे। एक सौ करोड़ इकट्ठा आने पर पेंशनर सरप्लस में डाल दिया जाएगा। इसमें सरकार से भी 200 करोड़ की मांग रख सकते हैं, जिसे पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन पहले फिर वेतन कर्मियों को दिया जाएगा, इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा।



धर्मशाला : स्कूल शिक्षा बोर्ड में आयोजित पेंशनर महामंथन सम्मेलन में बोलते बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा व उपस्थित पेंशनर्स। (नितिन)

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य विपदा से गुजर रहा है, आर.डी.जी. बंद कर दी गई है। लेकिन ओ.पी.एस. बंद नहीं होगी और अन्य सुविधाएं भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है कि बोर्ड को बुलंद करने वाले पूर्व कर्मचारियों को बुलाकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि मैडीकल बिल व अन्य समस्याओं को समय पर हल

किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा बोर्ड की अधिकतर फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे बेहतरीन कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने पेंशनरों से निवेदन किया है कि वे अपने उपयोगी सुझाव बोर्ड को लिखित रूप से ई-मेल व हार्ड कॉपी के रूप में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी व बोर्ड को आत्मनिर्भर निभाने के लिए भी लिख

सकते हैं। डॉ. शर्मा ने कहा कि वह खुद भी एच.पी. बोर्ड से पढ़े हैं और पूरे राज्य में छठा स्थान मिला था, इसमें भी पूर्व कर्मचारियों का ही हाथ था। पेंशनर्ज संघ की ओर से 2016 के बाद एरियर देय है, उसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैडीकल बिलों की जल्द अदायगी जारी रहेगी, डी.ए. 35 लाख के करीब जारी कर दिया गया है और लाइफ सर्टीफिकेट डिजिटल कर दिया गया है।

शिक्षा बोर्ड के पेंशनरों को मिलेगा डीए

धर्मशाला में अध्यक्ष डाक्टर राजेश शर्मा ने किया ऐलान, 35 लाख जारी, सरकार और विभाग के पास 85 करोड़ हैं पेंडिंग

दिव्य हिमाचल टीम - धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष की पहल पर बोर्ड पेंशनरों के लिए महामंथन एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सच्ची चौपाल व संवाद कार्यक्रम के तहत पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया। इस दौरान वर्ष 2016 के बाद लंबित देय एरियर को बोर्ड अध्यक्ष ने जल्द जारी किए जाने की बात कही। साथ ही मेडिकल बिलों की जल्द अदायगी जारी रहेगी, महंगाई भत्ते डीए के पेंशनरों के 35 लाख के करीब जारी कर दिए गए हैं, साथ ही लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल कर दिया गया है, जिससे कर्मियों को बिना बोर्ड में आए ही जीवन प्रमाण पत्र घर में ही अपने मोबाइल से बनाने की सुविधा मिल पा रही है। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा



धर्मशाला : पेंशनरों को सम्मानित करते शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर राजेश शर्मा

कि 85 करोड़ सरकार व शिक्षा विभाग से लेने को है, जो कि जल्द मिल जाने से बोर्ड वित्तीय संकट से उभर सकेगा।

चेयरमैन ने कहा कि सरकार की तरफ से पेंडिंग एक सौ करोड़ के लगभग इकट्ठा आने पर पेंशनरों सरप्लस में डाल दिया जाएगा। अब तक सरकार से शिक्षा बोर्ड को कोई भी ग्रांट नहीं मिलती है, हालांकि अब पेंशनरों सरकार से भी 200 करोड़ की मांग रख सकते हैं, जोकि मिलने पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि हर माह अब पेंशनरों को पहले पेंशन जारी की जाएगी, उसके बाद कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा।

डाक्टर राजेश ने सराहा पेंशनरों का संघर्ष-योगदान

धर्मशाला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान और संवेदना की एक नई इबारत लिख दी है। धर्मशाला में आयोजित समारोह में बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने पेंशनरों के लंबे संघर्ष और योगदान को सराहा। डा. शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बोर्ड में अब सबसे पहले पेंशनरों को पेंशन दी जाएगी, भले ही वर्तमान कर्मियों की सैलरी उसके बाद जारी हो। अध्यक्ष ने भावुक होते हुए कहा कि बोर्ड की आज जो भी उपलब्धियां हैं, वे इन समर्पित हाथों के अथक परिश्रम, ईमानदारी की नींव पर खड़ी हैं।



कर्मचारियों के वेतन से पहले मिलेगी पेंशन

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने समारोह में की घोषणा

पेंशन, मेडिकल बिल व अन्य प्रशासनिक कार्यों के निपटारे के लिए बनेगा सिस्टम

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मान और संवेदना दिखाकर पहल की है। बुधवार को आयोजित समारोह में बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने न केवल पेंशनर्स के लंबे संघर्ष और योगदान को सराहा, बल्कि एक ऐसी घोषणा की जिसने हाल में मौजूद हर शख्स को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। डा. शर्मा ने कहा, "बोर्ड में अब सबसे पहले पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी, भले ही वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी उसके बाद जारी हो।"

समारोह के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड की आज जो भी उपलब्धियां हैं, वे इन 'समर्पित हाथों' के अथक परिश्रम और ईमानदारी की नींव पर खड़ी हैं। उन्होंने पेंशनर्स को बोर्ड का 'जीवित



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में बुधवार को समारोह में उपस्थित पेंशनर्स। (दायें) इस दौरान उपस्थित बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा व अन्य • जागरण

इतिहास' करार देते हुए कहा कि बोर्ड अपने गुरुओं और पूर्व सहयोगियों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यह आयोजन महज एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने शिक्षा की नींव मजबूत की। उन्होंने कहा

कि 85 करोड़ रुपये सरकार व शिक्षा विभाग से लेने हैं। जल्द मिल जाने पर वित्तीय संकट से उभर जाएंगे। एक सौ करोड़ इकट्ठा आने पर पेंशनर सरप्लस में डाल दिया जाएगा। इसमें पूर्व कर्मचारी सरकार से 200 करोड़ की मांग रख सकते हैं, जिसे पेंशन फंड में डाल



दिया जाएगा।

तकनीक से थमेगा फाइलों का चक्कर : पेंशनर्स को समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों की धूल न फांकनी पड़े, इसके लिए बोर्ड अब हाईटेक होने जा रहा है। डा. शर्मा ने बताया कि एक ऐसी डिजिटल प्रणाली विकसित की जा

रही है, जिससे पेंशनर्स घर बैठे शिकायतों और फाइल की स्थिति जान सकेंगे। पेंशन, मेडिकल बिल और अन्य प्रशासनिक कार्यों के निपटारे के लिए समयबद्ध और पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की हल समस्या का समाधान किया जाएगा।

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष बोले-जारी रहेगा संवाद का सिलसिला

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ एक बार का सम्मान नहीं, बल्कि अब पेंशनर्स और बोर्ड प्रबंधन के बीच सीधा संवाद नियमित रूप से होगा। अध्यक्ष ने सभी पूर्व कर्मियों को खुला निमंत्रण दिया कि वे अपने सुझाव और अनुभव बोर्ड के साथ साझा करें। पेंशनर्स संघ के 2016 के बाद परियार देय है, उसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। मेडिकल बिलों की जल्द अदायगी जारी रहेगी, डीए 35 लाख के करीब जारी कर दिया है। समारोह के अंत में प्रदेश भर से आए पेंशनर्स को सम्मानित कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संगठन सचिव मनोहर टाकुर समेत अन्य मौजूद रहे।

बोर्ड पेंशनर्स के लिए अध्यक्ष की पहल, महामंथन कार्यक्रम का किया आयोजन

सरकार-शिक्षा विभाग से 85 करोड़ लेने को 200 करोड़ ग्रांट की रखेंगे मांग: डॉ. राजेश

◆ बोले, पेंशनर्स को कर्मचारियों के वेतन से पहले मिलेगी पेंशन

◆ धर्मशाला में सच्ची चौपाल में पेंशनर्स की समस्याओं का किया हल

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की पहल पर बोर्ड पेंशनर्स के लिए महामंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं, पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.



महामंथन कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा बोर्ड पेंशनर्स। **अनंत ज्ञान**

राजेश शर्मा ने कहा कि 85 करोड़ सरकार व शिक्षा विभाग से लेने को है, जोकि जल्द मिल जाने पर बोर्ड वित्तीय संकट से उभर सकेगा। एक सौ करोड़ इकट्ठा आने पर पेंशनर सरप्लस में डाल दिया जाएगा। सरकार से भी 200 करोड़ की मांग रख सकते हैं, जिससे पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन पहले फिर वेतन कर्मियों को दिया जाएगा, इस पर जल्द ही

अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विपदा के दौर से गुजर रहा है, आरडीजी बंद कर दी गई है, लेकिन ओपीएस बंद नहीं होगी, अन्य सुविधाएं जारी रहेगी। उन्होंने कहा पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है कि बोर्ड को बुलंद करने वाले पूर्व कर्मचारियों को बुलाकर सम्मानित किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा बोर्ड की अधिकतर फाइलों को डिजिटल कर

दिया गया है, जिससे बेहतरीन कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने पेंशनरों से निवेदन किया है कि वह अपने उपयोगी सुझाव बोर्ड को लिखित रूप से ईमेल व हार्ड कॉपी के रूप में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी व बोर्ड को आत्मनिर्भर निभाने के लिए भी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद भी एचपी बोर्ड से पढ़े हैं और पूरे राज्य में छटा स्थान मिला था, इसमें भी पूर्व कर्मचारियों का ही हाथ था। पेंशनर्स संघ की ओर से 2016 के बाद एरियर देय है, उसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। मेडिकल बिलों की जल्द अदायगी जारी रहेगी, डीए 35 लाख के करीब जारी कर दिया गया है व लाईफ सर्टिफिकेट डिजिटल कर दिया गया है।

सैलरी से पहले पेंशन! शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष की ऐतिहासिक घोषणा

Apka Faisla

19-02-2026

अब दफ्तरों के चक्करों से
मिलेगी मुक्ति-डॉ. राजेश शर्मा
का धर्मशाला में बड़ा ऐलान

धर्मशाला, (आपका फैसला)।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने
अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के
लिए सम्मान और संवेदना की एक
नई इबारत लिख दी है। धर्मशाला में
आयोजित एक गरिमामय समारोह में
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने न
केवल पेंशनर्स के लंबे संघर्ष और
योगदान को सराहा, बल्कि एक
ऐसी घोषणा की जिसने हॉल में
मौजूद हर शख्स को तालियां बजाने
पर मजबूर कर दिया। डॉ. शर्मा ने
स्पष्ट कहा, बोर्ड में अब सबसे पहले
पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी, भले
ही वर्तमान कर्मचारियों की सैलरी
उसके बाद जारी हो। पुरानी यादों
का सम्मान, नई व्यवस्था का
संकल्प समारोह के दौरान अध्यक्ष ने
भावुक होते हुए कहा कि बोर्ड की
आज जो भी उपलब्धियां हैं, वे इन
समर्पित हाथों के अथक परिश्रम
और ईमानदारी की नींव पर खड़ी हैं।
उन्होंने पेंशनर्स को बोर्ड का जीवित

इतिहास करार देते हुए कहा कि बोर्ड
अपने गुरुओं और पूर्व सहयोगियों
के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो
सकता। यह आयोजन महज एक
औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन
बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने
का अवसर है जिन्होंने शिक्षा की
नींव मजबूत की। पेंशनर्स को अपनी
समस्याओं के लिए कार्यालयों की
धूल न फांकनी पड़े, इसके लिए
बोर्ड अब हाई-टेक होने जा रहा है।
डॉ. शर्मा ने बताया कि एक ऐसी
डिजिटल प्रणाली विकसित की जा
रही है, जिससे पेंशनर्स घर बैठे
अपनी शिकायतों और फाइल की
स्थिति जान सकेंगे। पेंशन,
मेडिकल बिल और अन्य
प्रशासनिक कार्यों के निपटारे के
लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी
सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि
बुजुर्गों को अनावश्यक विलंब और
असुविधा का सामना न करना पड़े।
संवाद का सिलसिला रहेगा जारी
सिर्फ एक बार का सम्मान नहीं,
बल्कि अब पेंशनर्स और बोर्ड
प्रबंधन के बीच सीधा संवाद
नियमित रूप से होगा।

बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की पहल पर बोर्ड पेंशनर्स के लिए महामंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि 85 करोड़ सरकार व शिक्षा विभाग से लेने को है, जोकि जल्द मिल जाने पर बोर्ड वित्तीय संकट से उभर सकेगा। एक सौ करोड़ इकट्ठा आने पर पेंशनर सरप्लस में डाल दिया जाएगा। इसमें सरकार से भी 200 करोड़ की मांग रख सकते हैं, जिससे पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन पहले फिर वेतन कर्मियों को दिया जाएगा, इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है कि बोर्ड को बुलंद करने वाले पूर्व

■ बोर्ड अध्यक्ष ने पेंशनरों के लिए महामंथन कार्यक्रम के दौरान सुनी समस्याएं

कर्मचारियों को बुलाकर सम्मानित किया गया है। डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड के अहम निर्णयों पर अब सरकार के निर्देशों पर स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पेंशनरों से निवेदन किया कि वह अपने उपयोगी सुझाव बोर्ड को लिखित रूप से ईमेल व हार्ड कॉपी के रूप में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी व बोर्ड को आत्मनिर्भर निभाने के लिए भी लिख सकते हैं। डॉ. शर्मा ने कहा कि वह खुद भी एचपी बोर्ड से पढ़े हैं और पूरे राज्य में छठा स्थान मिला था, इसमें भी पूर्व कर्मचारियों का ही हाथ था। पेंशनर्स संघ की ओर से 2016 के बाद एरियर देय है, उसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। मेडिकल बिलों की जल्द अदायगी जारी रहेगी, डिए 35 लाख के करीब जारी कर दिया गया है व लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल कर दिया गया है।

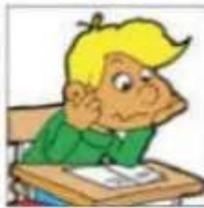
एक ही दिन दो परीक्षाएं, युवा असमंजस में

प्रदेश में नौ मार्च को जमा दो के फिजिक्स एग्जाम के साथ अग्निवीर फिजिकल टेस्ट

स्टाफ रिपोर्टर – धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं के साथ ही अग्निवीर फिजिकल टेस्ट एक ही तिथि में होने से युवा असमंजस में डाल दिए हैं। नौ मार्च को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से जारी डेटशीट के तहत जमा दो की फिजिक्स परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि सैन्य रिक्रूटमेंट रैली के तहत लिखित परीक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए अग्निवीर फिजिकल टेस्ट भी नौ मार्च को ही रखा गया है। ऐसे में तिथियों के क्लैस होने पर छात्रों ने शिक्षा बोर्ड से डेटशीट में आंशिक बदलाव की मांग रखी है, जबकि स्कूल शिक्षा

बोर्ड ने तिथि बदलने के बजाय विशेष मौके के तहत जून-जुलाई में वंचित रहने वाले छात्रों को परीक्षा का विकल्प प्रदान कर दिया है। ऐसे में परीक्षार्थियों



को एक बार फिर से असमंजस की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को वीरों की भूमि भी कहा जाता है, यहां के युवाओं में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा खूब देखने को मिलता है। भारतीय सैन्य रिक्रूटमेंट की ओर से अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लिखित परीक्षा पहले आयोजित की गई थी, जिसमें कई युवाओं ने उसे पास कर अब शारीरिक परीक्षा के

लिए बाजी मार ली है। हालांकि जमा दो में होने वाले कई युवा छात्रों के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है। अब फिजिकल परीक्षा

की तिथि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल तिथियों के साथ क्लैस हो गई है। इसमें नौ मार्च को कई युवाओं की शारीरिक परीक्षा के साथ ही जमा दो की फिजिक्स विषय की परीक्षा है। ऐसे में अब युवा संशय में हैं कि आखिर किस परीक्षा को तरजीह दें। इस संबंध में अभिभावकों की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को ईमेल से सूचित कर तिथियों में बदलाव करने की बात कही जा रही है। उधर, स्कूल शिक्षा

- छात्रों ने शिक्षा बोर्ड से डेटशीट में बदलाव की उठाई मांग
- बोर्ड ने तिथि बदलने के बजाय विशेष मौके में परीक्षा का दिया विकल्प

बोर्ड धर्मशाला के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की डेटशीट अढ़ाई माह पहले ही घोषित कर दी गई थी। बावजूद इसके इस तरह की स्थिति होने पर छात्रों को स्पेशल एग्जाम में परीक्षा देने का मौका प्रदान किया जाएगा। हालांकि अब तक उनके पास लिखित रूप से कोई इस तरह का प्रपत्र नहीं आया है।



एलडीआर के लिए शिक्षा बोर्ड ने रद्द किए 97 आवेदन

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निर्धारित फीस को जमान करने पर 22 फरवरी को होने वाली सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) के 97 आवेदन रद्द कर दिए हैं।

बोर्ड ने दिसंबर और जनवरी में इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड के पास 1,534 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रबंधन ने 1,437 आवेदन सही पाए



एलडीआर के लिए शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। बोर्ड ने बिना फीस आए 97 आवेदन रद्द कर दिए हैं। रद्द आवेदनों की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। - डॉ. मेजर विशाल शर्मा, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला

हैं। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक एलडीआर

के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 1,427 पदों के लिए लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 3,000 रुपये शुल्क जमा करवाने को कहा था।

ये पद केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवारत एसएमसी शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। इस दौरान जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो और जो एसएमसी नीति 17-07-2012 के तहत नियुक्त थे। ब्यूरो

किस पोस्ट के लिए अब कितने बचे आवेदन

आर्ट्स	296
इंग्लिश मास्टर	247
हिंदी	343
जेबीटी	60
मेडिकल	112
नॉन मेडिकल	102
संस्कृत	277

Pension before salary! Education Board Chairman's historic announcement

"Pensioners are our 'living history'"



SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA FEB 18 : The Himachal Pradesh School Education Board has written a new chapter of respect and compassion for its retired employees. In a solemn ceremony held in Dharamshala, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma not only acknowledged the long struggle and contribution of pensioners, but also made an announcement that brought applause from everyone present in the hall. Dr. Sharma clearly stated, "The Board will now pay pensions first, even if the salaries of current employees are released after that." During the ceremony, the Chairman became emotional and said that all the

achievements of the Board today are built on the foundation of the tireless hard work and honesty of these 'dedicated hands'. Describing pensioners as the "living history" of the Board, he said that the Board can never be free from the debt of its mentors and former colleagues. This event is not merely a formality, but an opportunity to express gratitude to the elders who strengthened the foundation of education. To ensure pensioners don't have to run to offices to resolve their issues, the Board is now going high-tech. Dr. Sharma explained that a digital system is being developed that will allow pensioners to check their complaints and file status from

the comfort of their homes. A timely and transparent system is being created for the settlement of pensions, medical bills, and other administrative matters, so that the elderly don't face unnecessary delays and inconvenience. This is not just a one-time honor; direct communication between pensioners and Board management will now take place on a regular basis. The Chairman extended an open invitation to all former employees to share their suggestions and experiences with the Board, so that the current system can be made more humane and responsive. At the end of the ceremony, pensioners from across the state were honored and thanked.